

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र.क. 1855/111/2014 विरुद्ध आदेश दिनांक 03.1.2013 पारित
द्वारा- कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ प्रकरण 48/पुनर्विलोकन/2012-13

- 1- संजय पुत्र वृजमोहन अग्रवाल
- 2- कमलेशकुमार पुत्र महेशचन्द्र लिखधारी
दोनों निवासीगण सी.पी.मिशन कम्पाउण्ड
झांसी, जिला झांसी उत्तरप्रदेश
- 3- ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र मुकुटविहारी
निवासी 1-0/1 परवाराना झांसी 30प्र0
- 4- गोपालदास पुत्र भगवानसिंह तौमर
- 5- श्रीमती सरला पत्नि किशोरी सौर
दोनों निवासी ढिमरपुरा तहसील ओरछा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश

---आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़

---अनावेदक

आवेदक के अभिभाषक श्री राजेन्द्र पटेरिया
म0प्र0शासन की ओर से कोई नहीं

आदेश

(आज दिनांक 21.8.2014 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र.क. 48/2012-13
पुनर्विलोकन मे पारित आदेश दिनांक 3-1-2013 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू
राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ ने पत्र
कमांक पुअ/टीक/शिका/कलेक्टर/321/11 दिनांक 21-7-11 लिखकर
कलेक्टर टीकमगढ़ को अवगत कराया कि श्रीमती परमिया पत्नि डरू
आदिवासी, केशव तनय डरू आदिवासी, रामेश्वर तनय डरू आदिवासी निवासी



पूनोलखास थाना दिगोड़ा जिला टीकमगढ़ का आवेदन जांच हेतु प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा है कि उ०प्र० झांसी जिले के सचिन गुप्ता, अमितु अग्रवाल ने मेरे पिता डरू तनय हरदास आदिवासी का अहरण कर पिता के नाम की भूमि की रजिस्ट्री कराने का संदेह होने एवं पिता की जमीन की रजिस्ट्री कराकर हत्या की आशंका है। आवेदकों के पिता के नाम प्रतापपुरा ओरछा में मौजा पटैती भूमि सवा तीन एकड़ है जिसके विक्रय करने के लिये कलेक्टर टीकमगढ़ से विक्रय की मंजूरी ली जाना और मंजूरी के समय बेंचने का अनुबंध कृपाराम यादव से किया जाने का लेख कराया है, जिससे समुचित कार्यवाही की जाकर अमल में लाई जावे। पुलिस अधीक्षक के इस पत्र को आधार पर मानकर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 48 पुर्नविलोकन/12-13 पंजीबद्ध किया तथा तत्कालीन कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ-21/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 26.4.2011 को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु सक्षम अनुमति प्राप्त की तथा महिला सरला पत्नि किशोरी सौर निवासी ढिमरपुरा तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ एवं देवेन्द्र कुमार दलमोत्रा पुत्र बल्देवराज निवासी झांसी को नोटिस देकर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 3-1-13 पारित किया एवं तत्कालीन कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 26-4-11 से भूमिस्वामी महिला सरला पत्नि किशोरी सौर निवासी ढिमरपुरा को भूमि सवा क्रमांक 2/5 में से उसके हिस्सा अनुसार अंश रकबा 2.549 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के विक्रय हेतु दी गई अनुमति निरस्त करते हुये आवेदक क्रमांक 1 से 4 के हित में हुये पंजीकृत विक्रय पत्र से अंतरण का संहिता की धारा 165 के अंतर्गत शून्य कर भूमि पूर्ववत विक्रेता महिला सरला पत्नि किशोरी सौर निवासी ढिमरपुरा के नाम करने के आदेश दिये। इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण ने आयुक्त, सागर सभाग, सागर के समक्ष अपील क्रमांक 515/अ-21/12-13 प्रस्तुत की, किन्तु

(Signature)

वाद में सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील आदेश दिनांक 6-6-14 से वापिस की गई, तदुपरांत आवेदकगण से कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 3-1-13 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ ने पत्र क्रमांक पुअ/टीक/ शिका/कलेक्टर/321/11 दिनांक 21-7-11 में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि विक्रेता श्रीमती सरला पत्नि किशोरी सौर निवासी ढिंमरपुर द्वारा आवेदक क्रमांक-1 से 4 के हित में गलत ढंग से अथवा अनियमितताओं के आधार पर ग्राम बबेरी जंगल की आराजी क्रमांक 2/5 के अंश रकबा 2.549 हैक्टर की भूमि का विक्रय किया है और जब पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन आवेदिका क-5 एवं अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 से सम्बन्धित नहीं है तथा बबेरी जंगल के भूमिस्वामी के संबंध में नहीं है - कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा बिना आधार पर के ग्राम बबेरी जंगल की आराजी क्रमांक 2/5 के अंश रकबा 2.549 हैक्टर के सक्षम अनुमति पर से हुये कय-विक्रय के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करना बेआधार कार्यवाही है।

5/ कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 48/2012-13 पुनर्विलोकन के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने यह प्रकरण अनावेदिका क-5 एवं देवेन्द्र कुमार दलमोत्रा के विरुद्ध पंजीबद्ध करके इन्हीं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अनावेदिका क-5 ने कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर बचाव में लेखी उत्तर दिनांक 24-5-12 प्रस्तुत किया है जो कलेक्टर के प्रकरण में पृष्ठ 71 पर संलग्न है जिसका अंश उद्धरण इस प्रकार है -



मेरे द्वारा रूपय 9,20,000/- में भूमि विक्रीत कर दी गई थी। विक्रय के वाद समस्त राशि मेरे द्वारा क्रेता से प्राप्त कर ली गई थी। मैंने उक्त भूमि बिना किसी दवाव के स्वेच्छा से विक्रीत की है। उक्त भूमि विक्रय करने के वाद मेरे पास ग्राम उत्रदमखोरा में दिनांक 21.2.11 को आराजी नं. 11/6 रकबा 0.559 है। एवं ग्राम प्रतापपुरा में दिनांक 21-2-11 को आराजी नं. 20/2 रकबा 0.315 है। और दिनांक 6-1-12 को आराजी नं. 20/2अ/5 रकबा 2.023 हैक्टर ग्राम प्रतापपुरा में कृषि योग्य उपजाऊ भूमि कय कर ली गई है।

आवेदिका क-5 की बबेरी जंगल की आराजी कमांक 2/5 के अंश रकबा 2.549 हैक्टर के क्रेता आवेदक कमांक 1 लगायत 4 हैं किन्तु कलेक्टर द्वारा उन्हें रिकार्डेड भूमिस्वामी होते हुये किसी प्रकार का सूचना पत्र जारी नहीं किया है और न ही सुनवाई का अवसर दिया है स्पष्ट है कि कलेक्टर का आदेश आवेदक कमांक 1 से 4 के विरुद्ध एकपक्षीय है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं माना जा सकता।

5/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से पाया गया है कि यह सही है कि वादग्रस्त भूमि की भूमिस्वामिनी सौर जाति का होकर अनुसूचित जनजाति वर्ग से है किन्तु यह भी सही है कि उसने कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष वादग्रस्त भूमि के विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन दिया है जिसमें उल्लेख किया है कि मौजा बबेड़ी जंगल की वादग्रस्त भूमि उत्रबड़-खाबड़ एवं पथरीली है जिस पर कृषि कार्य नहीं हो पा रहा है जिसके कारण इस भूमि को विक्रय करके अन्य सुविधाजनक कृषि योग्य भूमि कय करना चाहती है। आवेदिका ने भूमि विक्रय उपरांत अन्य ग्राम में भूमि कृषि योग्य भूमि भी कय कर ली है किन्तु कलेक्टर टीकमगढ़ ने आवेदिका द्वारा दिये गये बचाव उत्तर के तथ्यों के विपरीत जाकर आदेश दिनांक 3-1-13 पारित करना पाया गया है।

6/ कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन की जांच

[Handwritten signature]

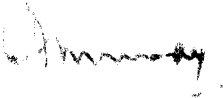
की जाच अधीनस्थ अधिकारियों से कराई है तहसीलदार ओरछा ने प्रतिवेदन दिनांक 21-4-11 में बताया है कि -

“ आवेदिका श्रीमती सरला पत्नि किशोरी सोर निवासी ग्राम ढिमरपुरा तहसील ओरछा के भूमि खसरा नंबर 2/2 रकबा 2.549 हैक्टर ग्राम ववेडीजंगल की भूमि उब्रल खावड़ तथा पथरीली होने के कारण उक्त भूमि विक्रय करने के उपरांत भी आवेदिका के पति किशोरी सोर के नाम ग्राम प्रतापपुरा में भूमि खसरा नंबर 20/2ब/2 रकबा 0.275 हैक्टर तथा ग्राम सावंतनगर में भूमि खसरा नंबर 11/7 रकबा 2.000 हैक्टर में सहखाते हैं। कुल रकबा 1.275 हैक्टर भूमि शेष बचती है आवेदिका भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आती है। अतः आवेदिका को ग्राम ववेडी जंगल के भूमि खसरा नंबर 2/5 रकबा 2.549 है0 भूमि म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) के अंतर्गत विक्रय करने की अनुमति शासन द्वारा निर्धारित गाईड लायन के अनुसार अनुमति दिया जाना उचित होगा। ”

तहसीलदार ओरछाएव अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 13 अ 21/10-11 में पारित आदेश दिनांक 26-4-11 से वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान की है। विचार योग्य बिन्दु है कि जब एक वार अनावेदिका क्र-5 रिकार्डेड भूमिस्वामी को भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान कर दी गई - आदेश के पालन में भूमि विक्रय हो गई, उसके बाद दिनांक दिनांक 16-8-11 को ऐसी कौनसी परिस्थितियों निर्मित हुईं जिनके कारण आदेश दिनांक 21.7.11 का पुनरावलोकन किया जाना अनिवार्य हुआ ? कलेक्टर टीकमगढ़ ने अंतरिम आदेश दिनांक 16-8-11 में पुनरावलोकन का आधार यह लिया है -

“ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा धारा 165 ख के अंतर्गत अनुमति दिये जाने के प्रकरण हैं जिसमें पट्टे की भूमि अन्य को हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई है। उक्त प्रकरणों में किस व्यक्ति को भूमि का हस्ताक्षरण किया जा रहा है एवं कितने दाम पर भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। ”

कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा उपरोक्त आधारों पर प्रकरण पुनर्विलोकन में लिया गया है। स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा जिन आधारों पर प्रकरण में पुनर्विलोकन



आदेश पारित किया है वह आधार ही वास्तविकता के विपरीत हैं।

6/ कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा विक्रय अनुमति हेतु पारित आदेश दिनांक 26.4.11 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश के अंतिम पद में इस शर्त पर विक्रय की अनुमति प्रदान की है -

“ अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर आवेदिका महिला सरला पत्नि किशोरी सोर निवासी ढिमरपुरा को ग्राम बबेड़ी जंगल की भूमि खसरा क्रमांक 2/5 रकबा 2.549 हे० भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रचलित गाइड लाइन के आधार पर विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है। ”

स्पष्ट है कि कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा विक्रय मूल्य , विक्रय दिनांक को प्रचलित गाई लाइन के मान से आदान प्रदान करने का आदेश दिया है और उप पंजीयक द्वारा भी विक्रय पत्र - विक्रय दिनांक को प्रचलित गाईड लाइन के मान से संपादित किया है तब पुनरावलोकन हेतु लिया गया उक्त आधार विरोधाभाषी होकर दुर्भावना अथवा किन्हीं अन्य मजदूरी / दवाव के कारण लिया जाना परिलक्षित है।

7/ कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.4.11 के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि को आवेदिका क-5 ने पंजीकृत विक्रय पत्र से आवेदक क्रमांक 1 से 4 को विक्रय कर दी, जबकि कलेक्टर टीकमगढ़ ने अंतरिम आदेश दिनांक 16.8.11 से आदेश दि. 26.4.2011 को पुनरावलोकन में लिये जाने का निर्णय लिया है, तब क्या अंतरिम आदेश दिनांक 16.8.11 के क्रम में पारित आदेश दिनांक 3-1-13 पूर्वदिश दिनांक 26.4.11 पर भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा ?

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 165 - ऐसा प्रावधान नहीं है कि विक्रय अनुमति प्रदान करने पर भूमि विक्रय -- तत्पश्चात् आदेश पारित कर पूर्वानुमति निरस्त करते हुये विक्रय पत्र भूतलक्षी प्रभाव से शून्य घोषित किया जा सके।

किन्तु कलेक्टर टीकमगढ़ ने उक्तानुसार तथ्यों पर गौर न करने की त्रुटि की है।



8/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि सदभावनापूर्वक आवेदन देकर आदेश दिनांक 26.4.2011 से वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति प्राप्त कर विक्रेता भूमिस्वामी ने कंतागण के हित में भूमि विक्रय की है। कय-विक्रय पत्र सदभावना पर आधारित है जिसे कारण तहसीलदार ने नामान्तरण आवेदन की पूर्ण जांच कर कंतागण का, कय की गई भूमि पर नामान्तरण किया है। विक्रय पत्र संपादित होने के उपरांत नामान्तरण किये जाने तक किसी भी पक्ष ने विक्रय मूल्य कम प्राप्त होने की शिकायत नहीं की है अपितु कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष विक्रेता ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत कर विक्रय पत्र विक्रय धन लेकर भूमि विक्रय करने का तथ्य बताया है एवं कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। कंता एवं विक्रेता के मन में बद्धान्ति न होने से कय - विक्रय सदभाविक पाकर नामान्तरण किया गया है। इन समस्त तथ्यों के होते हुये विक्रय अनुमति आदेश दिनांक 26.4.2011 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इसी आशय के न्यायिक दृष्टांत प्र.क 557/11/2013 में पारित आदेश दिनांक 21-5-12 में एवं अन्य प्रकरण क्रमांक 588/11/2013 में पारित आदेश दिनांक 16-7-13 में दिये गये हैं जिसके कारण कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/ पुर्नविलोकन/12-13 में पारित आदेश दिनांक 3-1-13 दोषपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/पुर्नविलोकन/12-13 में पारित आदेश दिनांक 3-1-13 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः वादग्रस्त भूमि पर विक्रय पत्र के आधार पर कंतागण के नाम की शासकीय अभिलेख में की गई प्रविष्टि यथावत् रहती है।


(अशोक शिवहरे)

सदस्य

राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर